PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Tue, 30 May 2017, Page 11
Width: 42.93 cms, Height: 23.11 cms, a3r, Ref: 44.2017-05-30.90

रेलवे ने तीन साल में खींचा विकास का व्यापक खाका

■ विनोद श्रीवास्तव

नई दिल्ली। एसएनबी

भविष्य में भारत में रेल की तस्वीर क्या होगी। इसका खाका मोदी सरकार के तीन साल में रेल मंत्रालय ने खींच लिया है। वर्ष 2022 में जब देश आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहा होगा तो इस बात की खुशी होगी ट्रेनों में बर्थ के लिए मारामारी नहीं मचेगी। रेलयात्रियों को 2022 में मांग के आधार पर ट्रेनों में बर्थ और सीटें मिल जाएंगी। इसके लिए रेल मंत्रालय ने अभी से रेललाइनों के विस्तार, विद्युतीकरण, स्टेशन विकास और डिब्बों के निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य शुरू कर दिया है। यहां तक की आने वाले कुछ वर्षों में देश में सेमी हाईस्पीड ट्रेन बड़ी संख्या में चलने लगेगी और बुलेट ट्रेन चलने की शुरुआत होने की बारी आ जाएगी।

नहीं मचेगी बर्थ के लिए मारामारी

आजादी के 75वें वर्ष 2022 में मांग के मुताबिक मिलेंगी सीट

दरअसल, रेल मंत्रालय ने रेलवे की आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए रेलवे के विकास का काम तेजी से शुरू कर दिया है। इसका परिणाम यह होगा कि वर्ष 2022 तक मांग के मुताबिक ट्रेनों में यात्रियों को बर्थ और सीटें मिलेंगी। समयसारिणी के अनुसार फ्रेट ट्रेनें चलेंगी और बाजार का 37 प्रतिशत माल ढुलाई का कार्य रेलवे के पास होगा। साथ ही रेलवे की आमदनी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी नॉन फेयर सोर्सेज के जरिए होगी। देश में रेल यातायात को लेकर कोई रुकावट या जाम की स्थिति नहीं होगी, बल्कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 16 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण हो जाएगा। मांग के अनुसार तीसरी लाइन और चौथी लाइनों का भी निर्माण हो जाएगा और 90 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि 95 प्रतिशत ट्रेनें समय पर चलने लगेंगी। मालगाड़ियों की औसतन गति 50 किलोमीटर और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रतिघंटे हो जाएगी। स्वर्णिम चतुर्भुज रेलमार्ग पर सेमी हाईस्पीड ट्रेनें चलने लगेंगी और वर्ष 2018 में बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरु आत हो जाएगी। बुलेट ट्रेन परियोजना की रफ्तार ठीक रही है तो वर्ष 2022 या 2023 तक बुलेट ट्रेन चलने की शुरुआत हो जाएगी।

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने मंत्रालय का प्रभार संभालते ही रेल की दशा और दिशा पर श्वेत पत्र पेश किया था। बीते वर्ष रेल बजट को समाप्त कर आम बजट में शामिल कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर देश की गति भी रेल से मिलेगी और प्रगति भी, का स्लोगन दिया है। रेलवे ने वर्ष 2017-18 में एक लाख 31 हजार करोड़ रुपए के निवेश की कार्ययोजना बनायी है। बीते तीन वर्ष 2014-15 में 58,716 करोड़ रुपए, वर्ष 2015-16 में 93,795 करोड़ रु पए और 2016-17 में एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश की कार्ययोजना बनाई गई थी। चुनौतियों और मुश्किलों के बीच 60 प्रतिशत रेल लाइन पर सौ फीसद यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ब्रॉडगेज रेल लाइन को बढ़ाया जा रहा है। 2017-18 में 35 सौ किलोमीटर ब्रॉडगेज विस्तार की योजना है। विद्युतीकरण में 2017-18 में चार हजार किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर में ब्रॉडगेज लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। यह यहां के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार में रेल मंत्रालय ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की शुरुआत कर दी है। दिल्ली-आगरा के बीच गतिमान एक्सप्रेस को 160 किलोमीटर प्रतिघंटा पर चलाया जा रहा है।